



# Skill Development Programme

## For Answer Writing

### Polity (Model Answer)

DATE : 14-July-2018

TIME : 06:30 pm

#### मुख्य परीक्षा

प्रश्न- उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, उच्च न्यायालय से किस प्रकार भिन्न है? चर्चा कीजिए।  
( 150 शब्द, 10 अंक )

**How the writ jurisdiction of Supreme Court is different from High Court? Discuss.**  
( 150 Words, 10 Marks )

#### MODEL ANSWER

उत्तर- संवैधानिक उपचारों संबंधी मूलाधिकार का प्रावधान अनुच्छेद-32 में किया गया है। यदि मूल अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो राज्य के विरुद्ध न्याय पाने के लिए संविधान के अनुच्छेद-32 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में और अनुच्छेद-226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में रिट (Writ) याचिका दाखिल करने संबंधी अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है।

उच्चतम न्यायालय की रिट संबंधी न्यायिक अधिकारिता क्षेत्र उच्च न्यायालय से निम्न रूपों में भिन्न है-

- ० उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इनके अलावा किसी अन्य उद्देश्य (कानूनी अधिकार के संबंध में) को लेकर भी जारी कर सकते हैं। इस तरह उच्चतम न्यायालय के रिट संबंधी न्यायिक अधिकार, उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है।
- ० उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य को या यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित हो तो वहाँ के खिलाफ ही जारी कर सकता है। इस तरह रिट जारी करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्रीय न्यायक्षेत्र ज्यादा विस्तृत है।
- ० अनुच्छेद-32 के अन्तर्गत, संवैधानिक उपचार अपने आप में मूल अधिकार है, इसलिए उच्चतम-न्यायालय अपने रिट न्यायक्षेत्र को नकार नहीं सकता है। वहाँ अनुच्छेद-226 के तहत उपचार विवेकानुसार है, इसलिए उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार भी सकता है। इस तरह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारण्टी देने वाला बनाया गया है।

अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

\* \* \*

